भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4079

जिसका उत्तर 12 अगस्त, 2026 को दिया जाना है।

21 श्रावण, 1948 (शक)

बढ़ते हुए एआई प्रतिभा पूल को ध्यान में रखते हुए एआई अनुसंधान वित्तपोषण

4079. श्री ई. तुकारामः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2025-26 और 2026-27 के दौरान इंडियाएआई मिशन के अंतर्गत बजट आवंटन और वास्तविक व्यय का ब्यौरा क्या है और मिशन के अनुमानित पाँच वर्षीय परिव्यय की तुलना में वर्ष 2026-27 में कम आवंटन किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन सहित प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत के कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) संबंधी निवेश और अनुसंधान एवं विकास व्यय का कोई तुलनात्मक आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भारत के बढ़ते हुए एआई प्रतिभा पूल को ध्यान में रखते हुए एआई अनुसंधान वित्तपोषण की पर्याप्तता का आकलन किया है;

(घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा आवंटित निधि का बेहतर उपयोग करने और एआई अनुसंधान और नवाचार को सुदृढ करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ड) क्या सरकार का इंडियाएआई मिशन के परिव्यय को बढ़ाने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क): इंडियाएआई मिशन को मार्च 2024 में पांच वर्ष की अवधि हेतु 10,371.92 करोड़ रु के परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया था, ताकि एआई कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर, फाउंडेशन मॉडल, डेटासेट, एप्लिकेशन, प्रतिभा विकास, स्टार्टअप फाइनेंसिंग और सुरक्षित और विश्वसनीय एआई को कवर करते हुए एक व्यापक स्वदेशी एआई इकोसिस्टम विकसित किया जा सके।

मिशन के तहत बजटीय आवंटन चरणबद्ध तरीके से किया गया है, जो पांच वर्ष की अवधि में समान रूप से वितरित किए जाने के बजाय अलग-अलग मिशन घटकों के कार्यान्वयन कार्यक्रम और अवशोषण क्षमता के अनुरूप है। मिशन के तहत वर्षवार बजटीय आवंटन इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	बजटीय आवंटन (करोड़ रु)
2024–25	173
2025–26	800
2026–27	1,000

(ख) से **(ङ):** सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वैश्विक निवेश की तीव्र गति और देश के बढ़ते एआई प्रतिभा आधार को ध्यान में रखते हुए भारत के एआई अनुसंधान, नवाचार और कंप्यूटिंग पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता से अवगत है।

इस दिशा में, सरकार ने भारत के एआई अनुसंधान और नवाचार इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने, स्वदेशी एआई क्षमताओं का निर्माण करने और देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए इंडियाएआई मिशन के तहत निम्नलिखित पहलें की हैं:

गणना:

- 15 कंप्यूट सेवा प्रदाताओं को चार चरणों में सूचीबद्ध किया गया है।
- सब्सिडी वाले कंप्यूट सपोर्ट के लिए 237 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें 93.18 लाख जीपीयू घंटे स्वीकृत किए गए हैं।
- एनआईसी डेटा सेंटर, शास्त्री पार्क, दिल्ली में लगभग 1.1 ईएफएलओपीएस के उच्च-प्रदर्शन एआई कंप्यूट सिस्टम के लिए एक खरीद आदेश जारी किया गया है।

संप्रभु मॉडल:

समर्थन के लिए 20 स्वदेशी फाउंडेशन मॉडल प्रस्तावों की पहचान की गई है, जिसमें 12 बड़े मल्टीमॉडल मॉडल और 8 लघु भाषा मॉडल शामिल हैं। पहले से लॉन्च किए गए उल्लेखनीय आउटपुट में निम्नलिखित शामिल हैं:

- सर्वम एआई (सर्वम 30बी/105बी, इंडस)
- भारतजेन (परम2 17बी टेक्स्ट, पत्रम 7बी वीएलएम, श्रुतम-2 एएसआर)
- ज्ञानी.एआई (5बी स्पीच टू स्पीच)
- 'वर्या' (इमेज एंड टेक्स्ट टू वीडियो जनरेशन)
- अवतार (वर्या 14बी डिस्टिल्ड वीडियो-जेन)
- न्यूरोडीएक्स (मानस 1 40 एम और 400 एम: न्यूरोलॉजिकल स्क्रीनिंग)
- जेंटिक (ब्रह्मएआई 1B टोकनाइज़र सूट)
- शोध एआई (1.6B मल्टी-स्केल फिजिक्स प्रोटोटाइप, एजेंटिक टूल कॉलिंग फ्रेमवर्क)

अनुप्रयोग विकास:

- 11 राष्ट्रीय स्तर के हैकथॉन/नवाचार चुनौतियां शुरू की गईं।
- सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में 20 एआई समाधान नियोजित किए गए हैं।

सुरक्षित और विश्वसनीय एआई:

- पूर्वाग्रह शमन, मशीन अनलर्निंग, गोपनीयता संरक्षण एआई, एल्गोरिदम ऑडिटिंग और व्याख्यात्मकता को संबोधित करने वाली 13 परियोजनाओं का चयन किया गया है।

<u>उत्कृष्टता केंद्र:</u>

- राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 58 एआई उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 22 को अब तक 13 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मंजूरी दी गई है और शुरू किया गया है।

<u>प्रतिभा विकास:</u>

- 178 संस्थानों में स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट कार्यक्रमों में 686 फेलोशिप प्रदान की गई।
- सभी के लिए युवा एआई कार्यक्रम 26.5 लाख से अधिक व्यक्तियों द्वारा पूरा किया गया।

<u>इंडियाएआई लैब्स:</u>

- 27 इंडिया डेटा और एआई लैब्स की स्थापना की गई, जो 3,500 से अधिक छात्रों के लिए प्रशिक्षण का समर्थन करती है।
- आईटीआई/पॉलिटेक्निकों में स्थापना के लिए 188 अतिरिक्त प्रयोगशालाओं की पहचान की गई है।

इस मंत्रालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन सहित अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत के एआई निवेश और अनुसंधान एवं विकास व्यय का कोई विशिष्ट तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं किया गया है। अब तक इंडियाएआई मिशन के अनुमोदित परिव्यय को बढ़ाने के किसी भी प्रस्ताव को औपचारिक रूप से अनुमोदित या अधिसूचित नहीं किया गया है।

*****